

न्यायालय जिला-कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.कां.अ)संख्या 52/2021 बउनवानी गजेन्द्र सिंह फौजदार बनाम लो.सू.अधि.एवं उपजिला कलेक्टर वजीरपु पुत्र श्री रामसिंह जाट, निवासी सैनिक नगर कॉलेज रोड़ गंगापुर सिटी

GCMS No-2021/135

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

तारीख हुकम

27.7.2021

पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्त नियत दिनांक को उपस्थित नहीं हुआ। सहायक लोक सूचना एवं उपजिला कलेक्टर वजीरपुर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्त द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 27.4.2021 को लोक सूचना अधिकारी एवं एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित किया जो अति० जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के पत्रांक एफ.2(93)सूकाअ/2021/846 दिनांक 30.4.2021 से लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला कलेक्टर वजीरपुर को अधिनियम की धारा 6(3) के तहत अन्तरित कर प्रार्थना पत्र में उल्लेखित निम्नांकित सूचनाएँ उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गया:-

1. श्री नरेन्द्र कुमार मीना उपजिला कलेक्टर वजीरपुर द्वारा स्वयं के आवास हेतु उपजिला कलेक्टर कार्यालय वजीरपुर के ऊपर बने कमरे व बरामदे में लेटबाथ,रसोई व अन्य निर्माण कराया है उसके लिए प्राप्त बजट व उस पर हुए खर्च के विवरण चाहिए एवं निर्माण करने का माह एवं वर्ष का विवरण चाहिए। दस्तावेज हो तो प्रमाणित सूचना दी जावे।
2. उक्त वर्णित निर्माण में जन सहयोग से प्राप्त राशि व सामग्री देने वालों का नाम पता व राशि एवं सामग्री का विवरण एवं खर्च का विवरण चाहिए। जिस अधिकारी के आदेश से राशि उगाई गयी है उसका व उगाने वाले अधिकारी/कर्मचारी का नाम व पद का विवरण चाहिए। नरेन्द्र कुमार मीना उपजिला कलेक्टर वजीरपुर द्वारा उक्त वर्णित आवास में निवास चालू करने का महीना व वर्ष का विवरण चाहिए।


प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर वजीरपुर द्वारा अपीलान्त को अन्दर मियाद उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर वजीरपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्त उपस्थित नहीं हुआ। दौरान सुनवायी उपस्थित पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर वजीरपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांक/सूचना का अधिकार/2021/973 दिनांक 20.7.2021 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि उक्त पत्र से वजीरपुर उपखण्ड कार्यालय के उपर किसी प्रकार का कोई नवीन निर्माण नहीं करवाने के कारण खर्च का विवरण दिया जाना सम्भव नहीं है तथा पीठासीन अधिकारी वर्तमान में शेरसिंह जाट के मकान में किराये पर रहते हैं के संबंध में वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। इसलिए अपील अपीलान्त खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

अपीलान्त द्वारा जरिये ई-मेल अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्त को जानबूझकर सूचना नहीं दी जा रही है जबकि उपजिला कलेक्टर शेरसिंह के मकान में नवम्बर-दिसम्बर,2020 में रहे थे उसके बाद कार्यालय के उपर प्रथम मकान स्थित कमरों के आगे बरामदे में पश्चिम दिशा की ओर के कमरे को फूडवाकर उसमें दरवाजा निकलवाया एवं कमरों के लिए लेटबाथ का निर्माण बरामदे में करवाया है साथ ही मध्य के कमरे में से बरामदे में दरवाजा निकालकर उसमें कमरे के अटैच एक स्टोर एवं रसोई बनायी गयी साथ ही खुले बरामदे को बन्द करवाकर उसमें आगे छत पर जाने के लिए लोहे का दरवाजा लगवाया एवं सैक्शन लगाया गया है उक्त सभी कार्य बिना उच्चाधिकारियों की अनुमति के स्वयं एवं स्टॉफ की सहायता से जन सहयोग से राशि व सामग्री एकत्रित कर करवाया गया

है। इस प्रकार श्री नरेन्द्र कुमार मीना उपजिला कलेक्टर द्वारा सरकारी भवन का उपयोग कर मकान किराया लिया जा रहा है तथा सरकारी बिजली का उपयोग किया जा रहा है। किन्तु प्रार्थी को कोई सूचना उपलब्ध नहीं करवायी गयी है। अतः सूचना उपलब्ध करवायी जावे।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत दिनांक 27.4.2021 को प्रेषित प्रार्थना पत्र में चाही गयी सूचना मुताबिक जवाब उपजिला कलेक्टर वजीरपुर के एडीओ कार्यालय के उपर कोई निर्माण कार्य नहीं करवाया है जिसके कारण खर्चे संबंधी विवरण दिया जाना सम्भव नहीं है तथा उपजिला कलेक्टर शेरसिंह जाट के मकान में किराये पर रहने की जानकारी अपीलान्ट को जरिये पत्रांक 973 दिनांक 20.7.2021 से उपलब्ध करवायी जा चुकी है। यद्यपि अपीलान्ट को लोक सूचना अधिकारी द्वारा चाही गयी सूचना के संबंध में वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया है किन्तु अधिनियम की तय समय सीमा 30 दिवस के स्थान पर लगभग 75 दिवस के उपरान्त अवगत कराया गया है जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि लोक सूचना अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रति गम्भीर नहीं है। जो उक्त अधिनियम एवं राजकार्य के प्रति उदासीनता का प्रतीक है। अतः लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में उक्त अधिनियम के तहत प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों का अधिनियम की तय समय सीमा में प्राथमिकता से निस्तारण किया जावे। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय में सुनवाया गया।


(राजेन्द्र किशन)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर